


विधान सभा सत्र जुलाई 2017 के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1533 के प्रश्नांश "क" की जानकारी  
बैठक दिनांक 24.07.2017 सदस्य - श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा

क्र०	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	जॉच अधिकारी का नाम/पदनाम	कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1	श्री जे.के.जैन	09.08.2011	प्लेट क्रमांक 353/1 एवं 333/1 का पूर्व अध्यक्ष द्वारा बेचने का प्रयास	श्री अनिल अग्रवाल सहकारी निरीक्षक	संस्था अध्यक्ष को प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर क्रमांक 3335 दिनांक 28.08.2011 से सिविल न्यायालय में रजिस्ट्री शून्य करने के निर्देश दिये गये।
2	श्री जे.के.जैन	28.09.2011	मुख्यालय के पत्र क्रमांक/गु.नि./11/942 दिनांक 12.09.11 के द्वारा शिकायत	श्री अनिल अग्रवाल सहकारी निरीक्षक	जाचक नं.3763/28.09.2011 से जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त
3	श्री जितेन्द्र कुमार जैन	19.03.2012	भ्रष्टाचार प्रकरण जॉच में सहकारिता विभाग के सतर्कता अधिकारी असमर्थ के कारण भ्रष्टाचार का प्रकरण लोकायुक्त को सौंपे जाने बाबत	श्री डी.आर.साठे अकेक्षण अधिकारी	1074/05.05.13 से जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त
4	श्री जे.के.जैन	28.06.2012	जनसुनवाई क्रमांक 80 दिनांक 20.07.2010 मूडबड क्रमांक 361/01 के सम्बंध में	श्री डी.आर.साठे अकेक्षण अधिकारी	3827 दिनांक 31.10.12 संस्था अध्यक्ष को निर्देश जारी किये।
5	श्री जे.के.जैन	19.11.2012	जनसुनवाई क्रमांक 80 दिनांक 20.07.2010 एवं 109 दिनांक 30.10.2012 के सम्बंध में	श्री डी.आर.साठे अकेक्षण अधिकारी	1078/28.01.13 से जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त
6	श्री जे.के.जैन	13.03.2013	संस्था की विभिन्न अनियमितता के सम्बंध में	श्री डी.आर.साठे अकेक्षण अधिकारी	प1078/28.01.13 से जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त।
7	श्री जे.के.जैन	10.05.2013	संस्था द्वारा अवैध रूप से विक्रय की जा रही संपत्ति पर रोक लगाई जाने बाबत	-	पत्र क्रमांक 1303/28.05.13 से वरिष्ठ उपपंजीयक (पंजीयन एवं मुद्रांक) कय विक्रय पर रोक लगाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
8	श्री जे.के.जैन एवं अन्य	14.11.2013	न्यायालय का आदेश पालन नहीं किया जाना बाबत	-	WP NO./ 7561 /2013 के पारित आदेश दिनांक 30.09.2013 के संबंध में प्रस्तुत अवमानना याचिका क्र-914/2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उप आयुक्त सहकारिता द्वारा की गई कार्यवाही को सामाधान कारक मानकर अवमानना याचिका DIPOSED OFF की गई।

  
संयुक्त आयुक्त  
सहकारिता, म.प्र.भारत

  
संयुक्त आयुक्त  
सहकारिता, म.प्र.भारत

श्री ० प्र० शासन,  
सहकारिता विभाग